भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3508
10.08.2026 को उत्तर के लिए

वन्यजीव संरक्षण के लिए वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी आधारित प्रणालियां

3508 **श्री मनोज तिवारीः**
श्रीमती शोभनाबेन महेन्द्रसिंह बारैयाः
श्री कोटा श्रीनिवास पूजारीः
श्री पी. पी चौधरीः
श्री आलोक शर्माः
श्रीमती महिमा कुमारी मेवाड़ः
श्री महेश कश्यपः
डॉ. संजय जायसवालः
श्री जनार्दन मिश्राः

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने वन्यजीव संरक्षण, जैव विविधता संरक्षण और मानव-वन्यजीव संघर्षों के प्रभावी प्रबंधन के लिए वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी आधारित प्रणालियों को सुदृढ़ करने के लिए कोई उपाय किए हैं, यदि हां, तो उन प्रमुख वन्यजीव संरक्षण कार्यक्रमों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है जिनमें ऐसी प्रौद्योगिकियों का उपयोग किया जा रहा है;

(ख) वन्यजीव संरक्षण योजना और जैव विविधता प्रबंधन के लिए वन्यजीव अपराधों की रोकथाम के लिए स्थापित उन्नत आनुवांशिक अनुसंधान सुविधाओं, डिजिटल जैव विविधता डाटाबेस और वन्यजीव सूचना प्रणालियों के उपयोग की वर्तमान स्थिति और प्राप्त प्रगति सहित ऐसी सुविधाओं की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार स्थिति क्या है

(ग) क्या वन्यजीव संरक्षण में अनुसंधान, न्यायिक विज्ञान क्षमताओं और साक्ष्य आधारित निर्णय को सुदृढ़ करने के लिए कोई संस्थागत तंत्र स्थापित किया गया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) इन पहलों से देश भर में विशेषकर राजस्थान में विशेष रूप से कुंभलगढ़ क्षेत्र, सीहोर जिले और भोपाल लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में जैव विवधता संरक्षण, वन्यजीव निगरानी और पारिस्थितिकीय प्रबंधन में किस प्रकार सुधार होने की संभावना है; और

(ङ) क्या सरकार राज्यों के बन विभागों, अनुसंधान संस्थानों, विश्वविद्यालयों और अन्य वैज्ञानिक संगठनों के सहयोग से वन्यजीव संरक्षण, जैव विविधता प्रबंधन, अनुसंधान, क्षमता निर्माण और तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देने के लिए कोई विशेष कार्यक्रम चला रही है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) और (ख) वन्यजीवों का प्रबंधन जिसमें मानव-पशु संघर्षों का शमन भी शामिल है, मुख्य रूप से संबंधित राज्य सरकार/ संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन की जिम्मेदारी है। राज्य सरकार/ संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन किसी भी संघर्ष की स्थिति में पहले प्रतिक्रियाकर्ता हैं।

वन्यजीव-पर्यावासों के समेकित विकास की केंद्र प्रायोजित योजना के अंतर्गत मंत्रालय राज्य सरकारों एवं संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन को मानव-वन्यजीव संघर्ष के प्रबंधन हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करता है, इस योजना के अंतर्गत *अन्य बातों के साथ साथ,* प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली की खरीद, सौर ऊर्जा संचालित विद्युत फेंसिंग, जैव- फेंसिंग, खाइयों तथा सीमाओं की दीवारों जैसे भौतिक अवरोधों का निर्माण एवं स्थापना, समस्याग्रस्त जंगली जानवरों को पकड़कर उनका पुनर्स्थापन, स्थानांतरित जानवरों के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे का विकास तथा ऐसे जंगली जानवरों की निगरानी एवं उन्हें आबादी वाले क्षेत्रों से दूर रखने जैसे कार्यकलापों के लिए सहायता प्रदान की जाती है।

इसके अतिरिक्त, सरकार ने मानव वन्यजीव संघर्षों के अलावा वन्यजीव और जैव विविधता संरक्षण के लिए वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी आधारित प्रणालियों को मजबूत करने के लिए कई उपाय किए हैं, जिसमें कैमरा ट्रैप, जीपीएस/उपग्रह आधारित रेडियो टेलीमेट्री, एम-एसटीआरआईपीईएस (M-STrIPES) जैसे स्मार्ट अनुप्रयोग, भौगोलिक सूचना प्रणाली, रिमोट सेंसिंग, निगरानी और निरीक्षण के लिए ड्रोन/यूएवी, अनुमान के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित प्रजाति पृथक्करण उपकरण, डॉल्फिन आकलन के लिए हाइड्रोफोन आदि शामिल हैं। इसके अलावा संरक्षण आनुवंशिकी का उपयोग वन्यजीव कॉरीडोर को मान्य करने, वन्यजीव अपराध का समाधान करने के साथ-साथ भारत के वन्यजीवों की आनुवंशिक संरचना का पता लगाने के लिए किया जा रहा है जो सक्रिय प्रबंधन और स्थानांतरण कार्यों की सुविधा प्रदान करता है।

(ग) और (घ) वन्यजीव संरक्षण का आधार वैज्ञानिक एवं साक्ष्य-आधारित जानकारी है, इसके अंतर्गत प्रजाति-विशिष्ट पहल एवं कार्य योजनाओं के साथ-साथ अखिल भारतीय बाघ आकलन के निष्कर्षों का भी नीतिगत निर्णय लेने एवं संरक्षण संबंधी योजनाओं के निर्माण में उपयोग किया जाता है।

(ङ) मंत्रालय देशभर में वन्यजीव संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए "वन्यजीव पर्यावासों का समेकित विकास" नामक केंद्र प्रायोजित योजना का संचालन करता है, इस योजना के अंतर्गत **"**वन्यजीव पर्यावासों का विकास**"** तथा "परियोजना बाघ एवं हाथी" जैसे घटक शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, मंत्रालय भारतीय वन्यजीव संस्थान, राज्य वन अनुसंधान संस्थानों तथा अन्य वैज्ञानिक संगठनों के माध्यम से वन्यजीव अनुसंधान एवं वैज्ञानिक अध्ययन को भी सहयोग प्रदान करता है।

****